



दैनिक समाचार पत्र भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया



एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पीएम मोदी ने पदक विजेताओं को दी बधाई

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026।
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के पदक अभियान को रविवार को नई उपलब्धियाँ मिलीं।

पुरुष एकल स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किया। अनाहत सिंह एशियन गेम्स में महिला एकल स्क्वैश में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। अभय सिंह ने भी पुरुष एकल में रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स में भी भारत का प्रभावी

एशियन गेम्स पदक का इंतजार समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। तेजस्विन और पारुल ने भी जीते कांस्य एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर ने पुरुष डेकाथलॉन में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 7,934 अंक के साथ स्पर्धा पूरी की। वहीं पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक जीता और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पोलियम पर जगह बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों खिलाड़ियों को भी बधाई दी। भारतीय पदक अभियान जारी 27 सितंबर तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के खाते में एशियन गेम्स में 37 पदक आ चुके थे, जिनमें चार स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य शामिल थे। खेलों में भारतीय दल की विभिन्न स्पर्धाओं में भागीदारी जारी है और आने वाले मुकामलों में पदक तालिका में और बदलाव संभव है। प्रधानमंत्री की ओर से खिलाड़ियों को दी गई बधाई में उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। इस बीच भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आगे की स्पर्धाओं के लिए मैदान में उतर रहे हैं।



प्रदर्शन एथलेटिक्स में एंसी सोजन ने महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता। उन्होंने 6.53 मीटर की छलांग लगाई और स्वर्ण पदक से केवल दो सेंटीमीटर पीछे रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन को सराहा। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक हासिल किया। यह उनका

एशियन गेम्स में पदार्पण भी था। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन की सराहना की। पुरुषों की ऊंची कूद में सरवेश कुशारे ने 2.25 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। उनकी उपलब्धि से पुरुष ऊंची कूद में भारत का लंबे अंतराल के बाद

एशियन गेम्स में पदार्पण भी था। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन की सराहना की। पुरुषों की ऊंची कूद में सरवेश कुशारे ने 2.25 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। उनकी उपलब्धि से पुरुष ऊंची कूद में भारत का लंबे अंतराल के बाद

सोने में तेज गिरावट, MCX पर 1.50 लाख रुपये से नीचे फिसला भाव

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026।
सोने की कीमतों में सोमवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना सात सप्ताह के निचले स्तर तक फिसल गया, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना कारोबार के दौरान 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया। MCX पर अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर्स कारोबार की शुरुआत में 1,50,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था, जबकि बाद में यह करीब 1,48,100 रुपये तक पहुंच गया। एक अन्य बाजार रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में अक्टूबर अनुबंध 1,47,989 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास भी



गोल्ड सोमवार को 3 प्रतिशत से अधिक गिरकर करीब 4,155 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। यह 5 अगस्त के बाद का सबसे निचला

स्तर बताया गया है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विश्लेषण के अनुसार सोने पर दबाव बढ़ने के पीछे कई वैश्विक कारक काम कर रहे हैं। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ाई है। इसके साथ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को ऊंचा रखने अथवा आगे बढ़ाने की संभावनाओं ने भी सोने की कीमतों को प्रभावित किया है। ब्याज दरों की आशंका से गैर-ब्याज वाली संपत्तियों पर दबाव सोना ऐसी संपत्ति है जो नियमित ब्याज आय नहीं देती। इसलिए जब

बाजार में ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना बढ़ती है और बॉन्ड यील्ड मजबूत होती है, तो सोने की मांग पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में कारोबार करने वाले सोने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान गिरावट के बीच बाजार की नजर आगे आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, महंगाई के संकेतकों, तेल की कीमतों, डॉलर की चाल और फेडरल रिजर्व की नीतिगत टिप्पणियों पर बनी हुई है। घरेलू बाजार में खुदरा कीमतें अलग हो सकती हैं भारत में सोने की खुदरा कीमतें केवल MCX के वायदा भाव पर निर्भर नहीं करतीं। शहर, सोने की शुद्धता, स्थानीय कर, बाजार की स्थिति और आभूषण निर्माण शुल्क के कारण अलग-अलग स्थानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है। इसलिए

आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए स्थानीय जौहरी की उसी दिन की दर, सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज और लागू करों को मिलाकर अंतिम कीमत की पुष्टि करना जरूरी है। आगे भी वैश्विक घटनाओं पर नजर सोने की कीमतों की अगली दिशा पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों का प्रभाव बना रह सकता है। विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी ब्याज दरों की अपेक्षाएं, डॉलर और भू-राजनीतिक घटनाक्रम बाजार के लिए प्रमुख संकेतक बने हुए हैं। ऐसे में मौजूदा गिरावट को देखते हुए सोने की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। निवेशकों और ग्राहकों के लिए किसी एक दिन के भाव के आधार पर निर्णय लेने के बजाय बाजार की व्यापक परिस्थितियों और अपनी जरूरत को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा।



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डॉंबिवली स्थित शास्त्री नगर नगरपालिका

अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों पर कथित हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना पार्षद रमेश सुकर्या म्हात्रे को बॉन्धे हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी। अदालत ने

उन्हें तीन दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारी लोगों की सेवा करते हैं तथा उनके साथ इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। 6 जुलाई की घटना से जुड़ा है मामला यह मामला 6 जुलाई 2026 को डॉंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। उपलब्ध अदालती और समाचार रिपोर्टों के अनुसार, एक गर्भवती महिला के उपचार को लेकर विवाद के बाद म्हात्रे और अन्य लोगों पर डॉक्टरों तथा अस्पताल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिपोर्टों के अनुसार, अस्पताल में नवजात गहन

चिकित्सा इकाई (NICU) में विस्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण महिला को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दिए जाने के बाद विवाद बढ़ा था। मामले की जांच के बाद आरोपपत्र भी दाखिल किया गया और आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट ने अगस्त में दी थी जमानत म्हात्रे को पहले निचली अदालत से जमानत मिली थी। इसके बाद बॉन्धे हाईकोर्ट ने मामले का कथित मारपीट से जुड़ा है। उपलब्ध अदालती और समाचार रिपोर्टों के अनुसार, एक गर्भवती महिला के उपचार को लेकर विवाद के बाद म्हात्रे और अन्य लोगों पर डॉक्टरों तथा अस्पताल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिपोर्टों के अनुसार, अस्पताल में नवजात गहन

लेकर कड़ा संदेश दिया। अदालत ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग लोगों की सेवा करते हैं और उन पर हमला नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान म्हात्रे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि म्हात्रे ने जांच और मुकदमे में सहयोग किया है। उनके पक्ष की ओर से पूर्व मामलों को लेकर अलग दलीलें भी रखी गईं। आरोपों पर अंतिम फैसला अभी बाकी सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश जमानत से संबंधित है। इससे मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम दोषसिद्धि या निर्दोषता का फैसला नहीं हुआ है। मुकदमे की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर आगे न्यायिक निर्णय लिया जाएगा। म्हात्रे के खिलाफ चल रहे मामले में अब उनके आत्मसमर्पण और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी। वहीं, अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा भी इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रमुखता से सामने आया है।

मुडल पालिया में गूंजा गणपति भक्ति का उल्लास, रंगोली विजेताओं का सम्मान

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
बेंगलुरु, 28 सितंबर 2026।

वातावरण बना रहा और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भगवान गणपति के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम



मुडल पालिया क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों द्वारा गणेश उत्सव श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव के दौरान क्षेत्र में धार्मिक

में मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र मुणोत उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर आयोजित

रंगोली प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को महेंद्र मुणोत ने पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से महेंद्र मुणोत का सम्मान भी किया गया। सम्मान के दौरान आयोजकों ने उनके कार्यक्रम में शामिल होने और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया। गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान गणपति की आराधना की। आयोजन में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता रही

तृणमूल के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 4 सप्ताह में दलीलें पूरी करने को कहा

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026।
तृणमूल कांग्रेस के नाम और आरक्षित 'फूल और घास' चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग के लिए निर्णय की समयसीमा तय कर दी। अदालत ने दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी दलीलें, जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। यह मामला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर दो गुटों के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर किसी गुट के पक्ष में पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। अदालत ने विवाद का अंतिम निर्धारण निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के माध्यम से करने का रास्ता स्पष्ट किया है। चार सप्ताह में पूरी करनी होगी



दलीलें और दस्तावेज चार सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा है। इसके बाद आयोग को तीन महीने में मामले पर फैसला करना होगा। इस तरह पूरी प्रक्रिया के लिए अदालत ने लगभग चार महीने की समयसीमा निर्धारित की है। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागवी और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने निर्वाचन आयोग के अंतरिम

आदेश और पार्टी के नाम तथा चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद का मुद्दा था। आयोग इन प्रस्तुतियों और संबंधित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तय समयसीमा में अपना निर्णय देगा। अदालत के निर्देश से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान अंतरिम व्यवस्था को पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। विवाद का अंतिम निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित चुनावी नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है। आगामी उपचुनावों की पृष्ठभूमि में मामला अहम पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों के लिए दोनों गुटों के उम्मीदवारों को अंतरिम रूप से अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई है। मतगणना 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद फिलहाल उपचुनावों के लिए लागू अंतरिम व्यवस्था बनी रहेगी, जबकि पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिन्ह पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब दोनों पक्षों को

निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने दावे और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आयोग इन प्रस्तुतियों और संबंधित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तय समयसीमा में अपना निर्णय देगा। अदालत के निर्देश से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान अंतरिम व्यवस्था को पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। विवाद का अंतिम निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित चुनावी नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है। आगामी उपचुनावों की पृष्ठभूमि में मामला अहम पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों के लिए दोनों गुटों के उम्मीदवारों को अंतरिम रूप से अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई है। मतगणना 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद फिलहाल उपचुनावों के लिए लागू अंतरिम व्यवस्था बनी रहेगी, जबकि पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिन्ह पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब दोनों पक्षों को



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नागोया, 28 सितंबर 2026।
जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने सोमवार को महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल

व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के पदक अभियान में एक और उपलब्धि जोड़ दी। बेहद रोमांचक फाइनल में ईशा ने कई शूट-ऑफ का सामना करते हुए पदक पक्का किया। स्वर्ण पदक के निर्णायक मुकाबले में चीन की

शियाओ जियारुइसुआन ने बाजी मारी। फाइनल की नियमित सीरीज के बाद ईशा और शियाओ दोनों ने 38-38 हिट थे। इसके बाद स्वर्ण पदक के लिए शूट-ऑफ हुआ, जिसमें चीनी निशानेबाज ने मामूली अंतर से बड़त बनाकर स्वर्ण अपने नाम किया और ईशा को रजत पदक मिला। लगातार शूट-ऑफ के बीच ईशा ने बनाए रखा संयम ईशा के लिए फाइनल आसान नहीं रहा। पदक की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें कई शूट-ऑफ से गुजरना पड़ा। वह दक्षिण कोरिया की किम ह्योन-सुक के साथ भी शूट-ऑफ में उतरीं और इसके बाद स्वर्ण के लिए शियाओ के सामने चुनौती पेश की। इस दौरान ईशा ने दबाव के बीच लगातार प्रदर्शन करते हुए पोलिडिम स्थान सुनिश्चित किया। फाइनल में ईशा ने 38 हिट का स्कोर बनाया। उत्तर कोरिया की किम ह्योन-सुक ने कांस्य पदक हासिल किया। टीम स्पर्धा के बाद व्यक्तिगत मुकाबले में वापसी ईशा सिंह का यह पदक इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि

महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत पदक से चूक गया था। व्यक्तिगत मुकाबले में ईशा ने क्वालिफिकेशन में 580 का स्कोर बनाकर फाइनल में जगह बनाई और इसके बाद चुनौतीपूर्ण फाइनल में रजत पदक हासिल किया। एशियन गेम्स में ईशा का यह लगातार दूसरा व्यक्तिगत 25 मीटर पिस्टल रजत पदक है। इससे पहले उन्होंने 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी इस स्पर्धा में रजत पदक जीता था। भारत के पदक अभियान में एक और इजाफा ईशा के रजत के साथ 28 सितंबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एशियन गेम्स में भारत की पदक संख्या 39 तक पहुंच गई थी। इसमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल थे। ईशा का रजत भारत के शूटिंग अभियान में भी एक और पदक जोड़ता है। भारतीय दल की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतियोगिता जारी है। ऐसे में आने वाले मुकाबलों के साथ भारत की पदक संख्या में बदलाव संभव है।

सम्पादकीय

बारिश से सूखे तक:भारत की जल–व्यवस्था

के सामने बदलती मौसम चुनौती

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारत में मानसून हमेशा से कृषि, जलापूर्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा रहा है। लेकिन बदलते मौसम के दौर में चुनौती केवल कम या अधिक बारिश की नहीं रह गई है। एक ही समय में देश के कुछ हिस्से भारी बारिश, बाढ़ और जलभराव से जूझते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में वर्षा की कमी जलसंकट और सूखे की स्थिति पैदा कर देती है। यह विरोधाभास भारत की जल–व्यवस्था, कृषि नियोजन और आपदा प्रबंधन के सामने एक गंभीर नीति प्रश्न खड़ा करता है। 28 सितंबर 2026 को केंद्र ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल भेजने की घोषणा की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार कर्नाटक में केंद्रीय दल 3 अक्टूबर को स्थिति का आकलन करेगा, जबकि महाराष्ट्र में भी दल भेजा जाएगा। महाराष्ट्र ने 358 में से 265 तहसीलों में सूखे की घोषणा की है और कर्नाटक ने 177 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। दूसरी ओर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 28 सितंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के मध्य भागों और मराठवाड़ा में भी गरज–चमक तथा तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। यही स्थिति भारत की जल–व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना सामने लाती है कहीं पानी समस्या बन रहा है और कहीं पानी की कमी। बारिश की मात्रा नहीं, उसका वितरण भी महत्वपूर्ण किसी राज्य या देश में वर्षा का औसत सामान्य होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि हर जिले, तहसील या गांव में पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। बारिश का समय, स्थान और तीव्रता भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यदि कम अवधि में अत्यधिक बारिश होती है तो उसका बड़ा हिस्सा तेज बहाव के साथ निकल सकता है। इससे खेतों में कटाव, शहरी जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जबकि कुछ सप्ताह या महीनों बाद वही क्षेत्र जलसंकट का सामना कर सकता है। इसके विपरीत, लंबे अंतराल में होने वाली सामान्य या मध्यम वर्षा भूजल पुनर्भरण और जलाशयों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। इसलिए भारत को केवल 'कितनी बारिश हुई' के बजाय 'कहां, कब और किस रूप में बारिश हुई' के आधार पर जल–योजना तैयार करनी होगी। सूखा केवल वर्षा की कमी नहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति यह भी बताती है कि सूखे का आकलन केवल वर्षा के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। मिट्टी में नमी, जलाशयों का स्तर, भूजल, सिंचाई की उपलब्धता और फसल की पानी की आवश्यकता को भी साथ में देखना होगा। केंद्र ने भी रबी फसल की योजना में 'वॉटर बजटिंग' को महत्वपूर्ण मानने की बात कही है। जल–संकट वाले क्षेत्रों में उपलब्ध पानी और मिट्टी की नमी के आधार पर फसल चयन करने तथा कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। यह दृष्टिकोण कृषि नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। किसान को केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के बजाय यह भी देखना होगा कि संबंधित क्षेत्र में उस फसल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है या नहीं। सिंचाई व्यवस्था में स्थानीय समाधान जरूरी भारत में सिंचाई का विस्तार हुआ है, लेकिन सभी कृषि क्षेत्रों को समान स्तर की सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्षा आधारित कृषि आज भी बड़ी आबादी की आजीविका से जुड़ी है। ऐसे क्षेत्रों में जल संरक्षण, खेत–तालाब, छोटे जलाशय, चेक डैम, वर्षाजल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसी स्थानीय व्यवस्थाएं अधिक प्रभावी हो सकती हैं। बड़ी परियोजनाओं की अपनी भूमिका है, लेकिन हर जल समस्या का समाधान बड़े बांध या लंबी पाइपलाइन में नहीं खोजा जा सकता। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। बाढ़ का पानी भी संसाधन है भारत में भारी बारिश के बाद अक्सर बाढ़ और जलभराव से होने वाले नुकसान की चर्चा होती है। निश्चित रूप से बाढ़ से जान–माल, सड़क, पुल, फसल और आवास को नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि वर्षा जल के सुरक्षित संचयन और भूजल पुनर्भरण की कितनी क्षमता विकसित की गई है। शहरों में प्राकृतिक जल निकासी मार्ग, झीलें और जलाशय अतिक्रमण या अव्यवस्थित विकास से प्रभावित होते हैं तो बारिश का पानी तेजी से बह जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संरक्षण संरचनाओं की कमी होने पर वर्षा जल का पर्याप्त संचयन नहीं हो पाता। इसलिए बाढ़ प्रबंधन और जल संरक्षण को दो अलग–अलग नीतियों मानने के बजाय एक–दूसरे से जोड़ना होगा। मौसम पूर्वानुमान से आगे बढ़कर स्थानीय तैयारी मौसम पूर्वानुमान में लगातार सुधार हो रहा है। 28 सितंबर को IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश, गरज–चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

डीप स्टेट की चर्चा:साजिश, सत्ता और सत्य के बीच कितनी दूरी?



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

राजनीतिक शब्दावली में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ से अधिक अपने प्रभाव के कारण चर्चा में आते हैं। “डीप स्टेट” भी ऐसा ही शब्द है। पिछले कुछ वर्षों में यह शब्द अमेरिका की राजनीति से निकलकर भारत सहित दुनिया के कई देशों की राजनीतिक बहस का हिस्सा बना है। कमी इसे सरकारी तंत्र के भीतर मौजूद कथित प्रभावशाली नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो कमी विदेशी हस्तक्षेप या किसी सरकार को अस्थिर करने की कथित रणनीति से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में मूल प्रश्न यह है कि इस शब्द के पीछे वास्तविक संस्थागत गतिविधियां कितनी हैं और राजनीतिक दावों की भूमिका कितनी? “डीप स्टेट” की अवधारणा सामान्यतः निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व से बाहर मौजूद

ऐसे अधिकारियों, सुरक्षा संस्थानों या प्रभावशाली समूहों के कथित नेटवर्क के संदर्भ में इस्तेमाल होती है, जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों। हालांकि, यह कोई ऐसी सार्वभौमिक और स्पष्ट कानूनी श्रेणी नहीं है जिसे हर देश में एक समान अर्थ में परिभाषित किया जा सके। अमेरिकी राजनीति में यह शब्द अलग–अलग राजनीतिक संदर्भों में अलग अर्थों में इस्तेमाल हुआ है। भारत में क्यों बड़ी चर्चा? दिसंबर 2024 में भारत में “डीप स्टेट” शब्द विशेष रूप से राजनीतिक चर्चा में आया, जब भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिकी विदेश विभाग और कथित “डीप स्टेट” तत्वों पर भारत को अस्थिर करने का आरोप लगाया। यह आरोप अमेरिकी वित्तीय सहायता और खोजी पत्रकारिता संगठन OCCRP से जुड़े विवाद के संदर्भ में लगाया गया

था। OCCRP ने अपने संपादकीय काम को स्वतंत्र बताते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार की कुछ फंडिंग का उसके संपादकीय निर्णयों पर नियंत्रण नहीं है। उस समय अमेरिकी विदेश विभाग, USAID और अन्य संबंधित पक्षों से भी प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं। यहां पत्रकारिता का पहला सिद्धांत सामने आता हैकृकिसी संगठन को मिलने वाली आर्थिक सहायता और, उसके संपादकीय निर्णयों के बीच संबंध का दावा अपने आप सिद्ध नहीं हो जाता। यदि किसी फंडिंग को राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रमाण बताया जा रहा है, तो यह देखना आवश्यक है कि पैसा किस उद्देश्य के लिए दिया गया, उसका उपयोग कैसे हुआ और क्या उसके बाद किसी विशिष्ट निर्णय या गतिविधि को निर्देशित किया गया। केवल संबंध या फंडिंग का अस्तित्व किसी बड़े षड्यंत्र का स्वतः प्रमाण नहीं है। बांग्लादेश का संदर्भ और सवालों की राजनीति फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में कथित अमेरिकी “डीप स्टेट” की भूमिका से संबंधित सवाल भी उठा था। उस संदर्भ में ट्रंप ने ऐसी भूमिका से इनकार किया था। दोनों देशों के नेताओं की बातचीत का व्यापक एजेंडा व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, रक्षा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित था। इस घटना से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती हैकृकिसी राजनीतिक दावे का अस्तित्व और उसका प्रमाणित होना दो अलग–अलग बातें हैं। राजनीतिक

मंच पर आरोप लगना समाचार हो सकता है, लेकिन आरोप स्वयं तथ्य नहीं बन जाता। प्रमाण और संदेह के बीच की रेखा लोकतंत्र में सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और प्रभावशाली संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। सत्ता से जुड़े किसी भी तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही की जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच का आधार दस्तावेज, आधिकारिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र स्रोत और सत्यापन योग्य घटनाक्रम होना चाहिए। मसलन, यदि किसी विदेशी संस्था ने किसी देश में कोई परियोजना वित्तपोषित की है, तो यह पूछना उचित है कि उसका उद्देश्य क्या था। लेकिन उससे सीधे यह निष्कर्ष निकाल देना कि वह किसी सरकार को गिराने या चुनाव प्रभावित करने की गुप्त योजना का हिस्सा थी, तब तक उचित नहीं होगा जब तक प्रमाण नहीं है। फरवरी 2025 में USAID से संबंधित एक अन्य विवाद इसका उदाहरण है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत में मतदाता भागीदारी के लिए 2.1 करोड़ डॉलर के कथित खर्च की बात सामने आई और भारत सरकार ने मामले की समीक्षा की बात कही। बाद में रिपोर्टों में यह सवाल भी उठा कि जिस राशि को भारत से जोड़ा जा रहा था, वह वास्तव में पड़ोसी बांग्लादेश के लिए निर्धारित थी। यही कारण है कि पत्रकारिता में “कहा गया”, “दावा किया गया”, “दस्तावेज में दर्ज है” और “स्वतंत्र रूप से सत्यापित हुआ”कृइन चारों वाक्यांशों के बीच

अंतर बनाए रखना जरूरी है। सोशल मीडिया ने चुनौती बढ़ाई सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार की गति कई गुना बढ़ा दी है। किसी वीडियो के लाखों व्यूज, किसी पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का बयान किसी दावे की सत्यता का प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर, किसी दावे को केवल इसलिए खारिज कर देना भी उचित नहीं कि वह असुविधाजनक या राजनीतिक रूप से विवादास्पद है। यहीं पत्रकारिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्रकार को न तो सत्ता के दावे का स्वतः प्रवक्ता बनना चाहिए और न विरोधी दावे को स्वतः सत्य मानना चाहिए। उसका काम उपलब्ध प्रमाणों को सामने रखना, संबंधित पक्षों का पक्ष लेना और पाठक को यह बताना है कि कौन—सी बात प्रमाणित है, कौन—सी आरोपित है और कौन—सी अभी जांच के दायरे में है। लोकतंत्र में पारदर्शिता ही वास्तविक कसौटी “डीप स्टेट” की बहस को केवल षड्यंत्र सिद्धांत बनाम सरकारी दावे के द्वंद्व में सीमित करना भी उचित नहीं है। असली प्रश्न संस्थागत पारदर्शिता का है। सरकारी संस्थाओं के निर्णय, विदेशी सहायता, राजनीतिक फंडिंग, लॉबिंग, सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां और सार्वजनिक धन के उपयोग पर लोकतांत्रिक निगरानी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही अफवाहों और अप्रमाणित दावों की गुंजाइश कम होगी। सत्ता चाहे निर्वाचित सरकार के पास हो या प्रशासनिक संस्थाओं

के पास, जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। अमेरिका में भी “डीप स्टेट” शब्द को लेकर सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर राजनीतिक बहस हुई है; वहीं आलोचकों ने ऐसे आरोपों को प्रशासनिक संस्थाओं के राजनीतिकरण के संदर्भ में देखा है। संपादकीय दृष्टि “डीप स्टेट” जैसे शब्दों की लोकप्रियता यह बताती है कि जनता सत्ता के दिखाई देने वाले ढांचे के पीछे काम करने वाली संस्थाओं और प्रभावों को समझना चाहती है। यह लोकतांत्रिक जिज्ञासा सकारात्मक है। लेकिन जिज्ञासा को निष्कर्ष में बदलने से पहले प्रमाण जरूरी है। आज आवश्यकता किसी एक राजनीतिक पक्ष के दावे को स्वीकार करने की नहीं, बल्कि दावों की जांच करने की संस्कृति को मजबूत करने की है। दस्तावेज क्या कहते हैं? संबंधित संस्था का आधिकारिक पक्ष क्या है? स्वतंत्र स्रोत क्या बताते हैं? घटनाओं के बीच वास्तविक संबंध क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण क्या उपलब्ध प्रमाण उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं? संपादकीय निष्कर्ष यही है कि “डीप स्टेट” पर बहस को न अंधविश्वास में बदलना चाहिए, न अंध–खंडन में। लोकतंत्र में आरोपों की जगह हो सकती है, संदेह की भी जगह हो सकती है, लेकिन अंतिम कसौटी प्रमाण और स्वतंत्र सत्यापन ही होना चाहिए। दावा अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह लेकिन पत्रकारिता की जिम्मेदारी इन सबसे ऊपर सत्यापन को रखना है।

दिल्ली का प्रदूषण:हर साल आपात कदम क्यों, स्थायी समाधान कब?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

दिल्ली की हवा में सर्दियों के साथ प्रदूषण का बढ़ना अब कोई नई घटना नहीं रह गई है। हर वर्ष अक्टूबर–नवंबर आते ही वाहनों, निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाने और आसपास के राज्यों में पराली जलाने को लेकर चिंता बढ़ती है। इसके बाद प्रतिबंधों और आपात उपायों का सिलसिला शुरू होता है। सवाल यह है कि यदि समस्या का समय लगभग हर वर्ष अनुमानित है, तो समाधान भी वर्षभर की स्थायी रणनीति के रूप में क्यों नहीं दिखाई देता? दिल्ली सरकार ने इस वर्ष सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से व्यापक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होने वाली शीतकालीन प्रदूषण कार्ययोजना में कार्यलयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम, कार्यालय समय में बदलाव, अधिकृत पार्किंग शुल्क दोगुना करने तथा धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण

एवं ध्वंस गतिविधियों पर विशेष रोक रहेगी, जबकि 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच और कड़े प्रतिबंध प्रस्तावित हैं। ये कदम प्रदूषण के चरम मौसम में तत्काल दबाव कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इनका वास्तविक मूल्यंकन इस आधार पर होना चाहिए कि क्या वे प्रदूषण के मूल स्रोतों को भी कम कर पाते हैं। प्रदूषण केवल दिल्ली की सीमा का विषय नहीं दिल्ली–एनसीआर की वायु गुणवत्ता को केवल राजधानी के भीतर होने वाली गतिविधियों से समझना पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम द्वारा समीक्षा किए गए विशेषज्ञ अध्ययन में PM2-5 को दिल्ली के वायु प्रदूषण में प्रमुख प्रदूषक बताया गया है। रिपोर्ट में स्थानीय उत्सर्जन के साथ क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण के आवागमन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। सर्दियों में परिवहन, उद्योग, बिजली संयंत्र और जैविक पदार्थों के जलने से बनने वाले द्वितीयक कण भी समस्या को प्रभावित करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि दिल्ली में केवल कुछ सप्ताह के लिए निर्माण रोकना या कार्यलयों में

उपस्थिति कम करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रदूषण जिस पूरे एयरशेड में बनता और फैलता है, उसके लिए दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित संबंधित क्षेत्रों के बीच लगातार समन्वित नीति की आवश्यकता है। वाहनों से होने वाला प्रदूषणरूप प्रतिबंध से आगे की नीति दिल्ली की परिवहन व्यवस्था प्रदूषण नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण सीमा का विषय नहीं दिल्ली–एनसीआर की वायु गुणवत्ता को केवल राजधानी का उपयोग और मालवाहक वाहनों की आवाजाही उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। सीएक्यूएम ने भी परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सड़क जाम कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। सरकार की नई योजना में पार्किंग शुल्क बढ़ाना और कार्यालयों के समय में बदलाव जैसे उपाय निजी वाहनों के उपयोग के साथ पीक–आवर दबाव को कम करने का प्रयास हैं। लेकिन इन उपायों की सफलता इस बात पर निर्भरे करेगी कि नागरिकों को पर्याप्त, सुविधाजनक और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन विकल्प भी उपलब्ध हों। यदि निजी

वाहन छोड़ने का संदेश दिया जाता है, तो बस, मेट्रो, अंतिम–मील कनेक्टिविटी, पैदल मार्ग और साइकिल जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को उसी अनुपात में मजबूत करना होगा। केवल आर्थिक दंड या प्रतिबंध से व्यवहार में स्थायी बदलाव की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है। निर्माण और सड़क की धूल पर निरंतर निगरानी जरूरी दिल्ली–एनसीआर में सड़क की धूल और निर्माण एवं ध्वंस गतिविधियों से होने वाला उत्सर्जन भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीएक्यूएम ने 2026 में सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वंस कचरे और धूल नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की है। मार्च 2026 तक हजारों स्थलों का निरीक्षण किया गया और नियमों के उल्लंघन वाले मामलों में बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए। यह बताता है कि केवल निर्माण रोकने के बजाय निर्माण स्थलों के संचालन के दौरान धूल नियंत्रण को पूरे वर्ष प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। ढंके हुए निर्माण क्षेत्र, सामग्री का उचित भंडारण, निर्माण मलबे का वैज्ञानिक निपटान, सड़क की नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के नियमों

का पालन केवल प्रदूषण के मौसम तक सीमित नहीं होना चाहिए। पराली किसान और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन हर साल सर्दियों में पराली जलाने को लेकर बहस तेज हो जाती है। यह समस्या केवल दंडात्मक कार्रवाई से हल नहीं होगी। किसानों के सामने फसल अवशेष के त्वरित निपटान, लागत और अगली फसल की तैयारी के लिए बाजार की घटनाओं को रोकने के लिए धूल, निर्माण एवं ध्वंस कचरे और धूल नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की है। मार्च 2026 तक हजारों स्थलों का निरीक्षण किया गया और नियमों के उल्लंघन वाले मामलों में बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए। यह बताता है कि केवल निर्माण रोकने के बजाय निर्माण स्थलों के संचालन के दौरान धूल नियंत्रण को पूरे वर्ष प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। ढंके हुए निर्माण क्षेत्र, सामग्री का उचित भंडारण, निर्माण मलबे का वैज्ञानिक निपटान, सड़क की नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के नियमों

और कचरा प्रबंधन भी बराबर महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण पर चर्चा अक्सर वाहन और पराली तक सीमित हो जाती है, जबकि औद्योगिक उत्सर्जन और खुद में कचरा जलाना भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सीएक्यूएम ने उद्योग, परिवहन, धूल, अपशिष्ट प्रबंधन और बायोमास जलाने सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए वार्षिक कार्ययोजनाओं पर जोर दिया है। आयोग ने वर्षभर निगरानी और प्रवर्तन को भी आवश्यक बताया है। यहां स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कचरे का नियमित संग्रह, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, खुले में कचरा जलाने पर प्रभावी रोक और निर्माण मलबे के व्यवस्थित निपटान के बिना वायु गुणवत्ता सुधार की रणनीति अधूरी रहेगी। संपादकीय दृष्टिकोण दिल्ली का प्रदूषण किसी एक विभाग, एक राज्य या एक मौसम की समस्या नहीं है। यह परिवहन, शहरी नियोजन, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और मौसम विज्ञान से जुड़ी बहुस्तरीय चुनौती है। इसलिए नीति का केंद्र केवल “प्रदूषण बढ़ने पर प्रतिबंध” नहीं, बल्कि “प्रदूषण बनने से पहले स्रोत पर नियंत्रण” होना चाहिए।

ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौती:कोयला, सौर ऊर्जा और बढ़ती बिजली मांग

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। उद्योग, कृषि, शहरीकरण, डिजिटल सेवाओं, परिवहन और घरेलू उपभोग हर क्षेत्र की निर्भरता बिजली पर बढ़ी है। ऐसे समय में बिजली की उपलब्धता केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और जनजीवन की निरंतरता का आधार बन चुकी है। हाल के दिनों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार को लेकर सामने आई चिंताओं और बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार का 50 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले 112 कैप्टिव कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध अधिकतम क्षमता पर चलाने का निर्देश इसी चुनौती की ओर संकेत करता है। इन संयंत्रों से कैप्टिव उपयोग के बाद बची बिजली को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से उपलब्ध कराने को भी

कहा गया है। कोयला संकट या आपूर्ति–श्रृंखला की चुनौती? वर्तमान स्थिति को सीधे–सीधे देश में कोयले की कमी कहना पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। कोयला मंत्रालय ने हाल में कहा है कि देश में कोयले की उपलब्धता पर्याप्त है और बिजली संयंत्रों तक आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। दूसरी ओर, ताप विद्युत संयंत्रों के स्तर पर भंडार में कमी और कोयला परिवहन से जुड़ी बाधाओं की रिपोर्टें सामने आई हैं। क्रिसिल के सितंबर विश्लेषण के अनुसार अगस्त 2026 में ताप विद्युत संयंत्रों का कोयला भंडार सालाना आधार पर लगभग 42 प्रतिशत घटकर 29 मिलियन टन रह गया और औसत स्टॉक कवर करीब नौ दिन रहा। विश्लेषण ने इसे मुख्यतः लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति–श्रृंखला से जुड़ी समस्या बताया, न कि संरचनात्मक कोयला संकट। यही अंतर नीति–निर्माण के लिए बिजली को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से उपलब्ध कराने को भी

परिवहन, रेल रोक, खनन क्षेत्र की परिस्थितियों या अन्य कारणों से बिजली संयंत्रों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो समस्या उत्पादन क्षमता से अधिक आपूर्ति–श्रृंखला की दक्षता की है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ केवल अधिक कोयला उत्पादन नहीं, बल्कि खदान से बिजली संयंत्र तक विश्वसनीय और समयबद्ध आपूर्ति का तालक और उसकी सीमा भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षमता विकसित की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार जुलाई 2026 में देश में 3,136.28 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ी गई और उस महीने नवीकरणीय स्रोतों से 56.25 अरब यूनिट बिजली उत्पादन दर्ज किया गया। उसी महीने देश की अधिकतम पूरी की गई बिजली मांग 270.203 गीगावाट रही। लेकिन सौर ऊर्जा की प्रकृति को भी समझना होगा। दिन में सूर्य की उपलब्धता के कारण सौर उत्पादन बढ़ सकता है, जबकि शाम और रात में इसकी

उपलब्धता स्वाभाविक रूप से घट जाती है। इसलिए केवल स्थापित सौर क्षमता बढ़ा देना चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली की गारंटी नहीं से अधिक आपूर्ति–श्रृंखला की दक्षता की है। सौर ऊर्जा की भूमिका नवीकरणीय बिजली को संग्रहित कर मांग के अधिक दबाव वाले समय में इस्तेमाल किया जा सके। जलविद्युत और भंडारण की अहम भूमिका ऊर्जा संक्रमण की चर्चा में जलविद्युत को अक्सर अपेक्षाकृत कम महत्व मिलता है, जबकि ग्रिड संतुलन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार जलविद्युत संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के बीच मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने में उपयोगी है तथा कई परियोजनाओं की भंडारण क्षमता उन्हें बिजली प्रणाली में लचीलापन प्रदान करती है।

इसलिए भारत की ऊर्जा रणनीति को केवल “कोयला बनाम सौर” के द्वंद्व तक सीमित करना उचित नहीं होगा। कोयला स्थिर और मांग के अनुरूप बिजली देने की क्षमता प्रदान करता है, सौर और पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करते हैं, जबकि जलविद्युत और ऊर्जा भंडारण इन स्रोतों के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। कोयले के भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई ऊर्जा संक्रमण का अर्थ यह नहीं कि भारत तत्काल कोयला आधारित बिजली से पूरी तरह अलग हो सकता है। बिजली मंत्रालय की 2025–26 वार्षिक रिपोर्ट में भी नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के देखते हुए कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में 2034–35 तक कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता का अनुमान भी दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत को संक्रमण के दौरान दो समानांतर लक्ष्यों पर काम करना होगाकृएक ओर

विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरी ओर ऊर्जा मिश्रण में स्वच्छ स्रोतों तथा भंडारण की हिस्सेदारी बढ़ाना। इस प्रक्रिया में पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण, दक्षता सुधार, लचीले संचालन और उत्सर्जन नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोयला आधारित संयंत्रों के लचीले संचालन और रैंप–रेट अनुपालन से संबंधित अध्ययन और ढांचे पर भी काम आगे बढ़ाया है। संपादकीय दृष्टिकोण भारत के सामने विकल्प किसी एक ऊर्जा स्रोत को चुनने का नहीं, बल्कि विश्वसनीय, किफायती और क्रमिक आवश्यकता के समय उपलब्ध कोयला आधारित क्षमता का अधिकतम उपयोग व्यावहारिक कदम हो सकता है, लेकिन इसे दीर्घकालीन ऊर्जा नीति का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। सबसे पहले कोयला आपूर्ति में बिजली की मांगबूत करना होगा। खदानों में उपलब्धता, रेल

परिवहन, बंदरगाहों, रैक की उपलब्धता और बिजली संयंत्रों के स्टॉक की निगरानी को एकीकृत व्यवस्था हो जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण में समान गति से निवेश आवश्यक है। तीसरा, जलविद्युत और पंचड–स्टोरेज परियोजनाओं को ग्रिड की आवश्यकता के अनुरूप विकसित करना होगा। इसके साथ बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, ग्रिड का आधुनिकीकरण और राज्यों के बीच बिजली के बेहतर आदान–प्रदान पर भी ध्यान देना होगा। केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; बिजली को सही समय और सही स्थान तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। निष्कर्ष ऊर्जा सुरक्षा का रास्ता संतुलित मिश्रण से आज की परिस्थिति भारत को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है ऊर्जा सुरक्षा किसी भी बिजली की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण आधार बना रह सकता है,

लेकिन दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण सहित विविध स्रोतों का संतुलित विकास आवश्यक है। भारत को ऐसी बिजली व्यवस्था बनानी होगी जो 24 घंटे उपलब्ध, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और भविष्य की पर्यावरणीय जरूरतों के अनुरूप हो। वर्तमान में कैप्टिव संयंत्रों से अतिरिक्त बिजली लेने का कदम तत्काल आपूर्ति दबाव को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि इस अस्थायी उपाय के साथ भारत ग्रिड, भंडारण, परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा में दीर्घकालीन निवेश कितनी तेजी से बढ़ाता है। ऊर्जा सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि देश के पास पर्याप्त बिजली हो; लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर समय, हर क्षेत्र और हर वर्ग तक विश्वसनीय बिजली पहुंचे और विकास की रफ्तार ऊर्जा संकट से बाधित न हो।

जैन समाज, मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध: डी.के. शिवकुमार



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026।
तुबहल्ली स्थित श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित क्षमावाणी महापर्व एवं अभिनंदन समारोह श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन कर पूजा-अर्चना एवं आरती की। इसके बाद उन्होंने निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज ससंध के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के

आगमन पर जैन समाज एवं आयोजन समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य के सभी जैन समाजों, जैन मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों से जुड़े हितों एवं संरक्षण के विषयों पर आवश्यक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज की ओर से रखे गए विभिन्न विषयों और मांगों पर सरकार स्तर पर विचार करने की बात भी कही। कर्नाटक की जैन विरासत का किया स्मरण मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के इतिहास और जैन परंपरा के बीच रहे संबंधों का उल्लेख

कुमावत नाम को स्वतंत्र रूप से दर्ज करने की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026।
कुमावत समाज की ओर से सोमवार

ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि 'कुमावत' नाम को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में स्वतंत्र प्रविष्टि के रूप में दर्ज करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे समुदाय के लोगों को दस्तावेजों और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। राज्य सरकार को सूचित करने का आश्वासन समाज

प्रतिनिधियों के अनुसार, ज्ञापन पर राज्यपाल की ओर से मामले को राज्य सरकार के संज्ञान में लाने तथा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की दिशा में प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया गया। हालांकि, कर्नाटक की सरकारी सूचियों में किसी समुदाय की OBC स्थिति या प्रविष्टि का निर्धारण संबंधित सरकारी प्रक्रिया और अधिसूचनाओं के आधार पर



करते हुए होयसल, कदंब और राष्ट्रकूट राजवंशों तथा आदिकवि पंथ की परंपरा को याद किया। उन्होंने श्रवणबेलगोला सहित राज्य के विभिन्न जैन मंदिरों और बसदियों को कर्नाटक की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताया। उन्होंने भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को कर्नाटक की आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक बताते हुए कहा कि भगवान बाहुबली का जीवन त्याग, आत्मसंयम, शांति और आत्मविजय का संदेश देता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मरण समारोह में राष्ट्रसंत आचार्य श्री 108 विद्यासागर

जी महाराज का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस दौरान शिक्षा, स्वावलंबन, जीवदया और सामाजिक सेवा से जुड़ी उनकी प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। जैन समाज की ओर से मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरण चिन्ह भेंट किए गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। यह अवसर आचार्यश्री के तप, त्याग, संयम और समाजसेवा के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। ^Quest for Happiness* के कन्नड़ संस्करण का विमोचन समारोह का प्रमुख

छठ पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, आयोजन समिति का गठन 15-16 नवंबर को होगा महोत्सव

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026।
लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा महोत्सव 2026 के आयोजन के तैयारियों को लेकर भोजपुरी समाज सेवा समिति (रजि.), बैंगलुरु की विशेष बैठक इंदिरानगर स्थित प्रधान कार्यालय



आकर्षण निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज द्वारा रचित 'Quest for Happiness' के कन्नड़ संस्करण का विमोचन रहा। आयोजकों के अनुसार, कन्नड़ में पुस्तक के प्रकाशन से जैन आध्यात्मिक चिंतन और जीवन-दृष्टि को व्यापक समाज तथा विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। क्षमा को जीवन का स्थायी संस्कार बनाने का संदेश क्षमावाणी महापर्व के अवसर पर निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज ने क्षमा के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने क्षमा को केवल औपचारिकता न मानकर आत्मपरिष्कार और आंतरिक परिवर्तन की साधना बताया। उन्होंने मनुष्य को क्रोध, अहंकार, वैर और अन्य कषायों को पहचानकर उनसे मुक्त होने का प्रयास करने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार, क्षमा केवल एक दिन की भावना न रहकर जीवन का स्थायी संस्कार बने, तभी क्षमावाणी की सार्थकता है। जनप्रतिनिधियों और समाज पदाधिकारियों की मौजूदगी समारोह में राज्यसभा सांसद एवं

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने भी वीरसागर जी महाराज ससंध के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य बी.के. हरिप्रसाद, विधायक एम. नारायणस्वामी, विधायक गणेश प्रकाश हुक्करी, विधान परिषद सदस्य रामोजी गौड़ा, डी.के. मोहन बाबू, एच. नागेश, उदयकुमार, विनोद और संतोष सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। आयोजन समिति की ओर से परम संरक्षक अनिल सेठी, श्री ज्ञानोदय ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश बरया एवं मुकेश भाईजी, आत्म सिलिकॉन वर्षायोग समिति के अध्यक्ष वैभव जैन, महामंत्री भानु जैन तथा प्रशासनिक समिति के अंकुर जैन और आशीष जैन सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह का समापन 'मिच्छामि दुक्कडम्' की पावन भावना के साथ हुआ। कार्यक्रम में क्षमा, मैत्री, विनम्रता और सेवा को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया गया। समाचार प्रेषक विपिन कुमार जैन, बैंगलुरु

छठ पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, आयोजन समिति का गठन 15-16 नवंबर को होगा महोत्सव

आयोजन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक में कोर टीम के सदस्यों ने महोत्सव को सुव्यवस्थित एवं व्यापक स्तर पर आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में अनुपस्थित सदस्यों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई तथा आगामी प्रत्येक रविवार को होने वाली तैयारियों संबंधी बैठकों में सहभागिता का आग्रह किया गया। पदाधिकारियों को जिम्मेदारियों के बेहतर निर्वहन का आह्वान संस्थापक अध्यक्ष संजय सिंह उज्जैन ने समिति के वर्तमान पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी से अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने और आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका

सुरागों की तलाश, टीम भावना का कमाल: WOW 2026 ट्रेज़र हंट में चिवड़ा टीम विजेता

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 27 सितंबर 2026। जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो की टीम उमंग की ओर से WOW 2026 'वॉक, ऑब्जर्व, विन' ट्रेज़र हंट का आयोजन उत्साह और रोमांच के साथ किया गया। आयोजन में 36 सदस्यों ने छह टीमों में शामिल होकर विभिन्न सुरागों, चुनौतियों और गतिविधियों में भाग लिया। ट्रेज़र हंट के दौरान प्रतिभागियों ने एम.जी. रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट और म्यूजियम रोड सहित शहर के प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित सुरागों की तलाश की और उनसे जुड़ी चुनौतियों को पूरा किया। गतिविधियों के



माध्यम से प्रतिभागियों की टीमवर्क, अवलोकन क्षमता, त्वरित निर्णय लेने और आपसी समन्वय जैसी क्षमताओं को प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगिता के परिणाम में चिवड़ा टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि भाकरवाड़ी टीम उपविजेता रही। कार्यक्रम के समापन पर पाकशाला में नाश्ते का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने आपसी सौहार्द और उत्साह के साथ कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष-एलओ जेसी रोनक नागोरी और उपाध्यक्ष-जी एंड जी जेसी श्वेता राखेचा का सहयोग रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व परियोजना समन्वयक जेसी संजना जैन और परियोजना निदेशक आर्ची जैन ने किया। आयोजन में जेसी धृति जैन और खुशी राखेचा का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष जेसी ललिता बोथरा, पूर्व अध्यक्ष जेसी सुनील मेहर, सचिव जेसी रीना गांधी और कोषाध्यक्ष जेसी दीपिका जैन के मार्गदर्शन में टीम उमंग द्वारा किया गया। "WOW 2026" के माध्यम से सदस्यों को मनोरंजन और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों के साथ एक-दूसरे के साथ जुड़ने तथा सहयोग और टीम भावना को मजबूत करने का अवसर मिला। समाचार प्रेषक रूपचंद जैन कुमट, बैंगलुरु।

छठ पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, आयोजन समिति का गठन 15-16 नवंबर को होगा महोत्सव

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने इंदिरा गांधी भवन में आयोजित मीडिया सम्मेलन में राज्य

लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सामूहिक सहयोग से आयोजन का संकल्प बैठक के समापन पर संजय सिंह उज्जैन ने नवगठित टीम को शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक सहयोग, समर्पण और अनुशासन के साथ छठ पूजा महोत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने भोजपुरी समाज, समिति के सदस्यों, सहयोगियों और श्रद्धालुओं से आयोजन में सक्रिय सहभागिता की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों एवं समाजसेवियों ने महोत्सव के आयोजन के लिए अपनी ओर से सहयोग राशि देने की घोषणा भी की। समिति ने विश्वास जताया कि समाज की सामूहिक सहभागिता से छठ पूजा महोत्सव श्रद्धा, सेवा, संस्कार और सामाजिक एकता का अवसर बनेगा। समाचार प्रेषक संजय कुमार सिंह उज्जैन, बैंगलुरु।

84 विधानसभा क्षेत्रों में 84 दिन चलेगी भारत जोड़ो यात्रा 2.0: बी.के. हरिप्रसाद

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने इंदिरा गांधी भवन में आयोजित मीडिया सम्मेलन में राज्य



में प्रस्तावित 'भारत जोड़ो यात्रा 2.0' को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 30 सितंबर से शुरू होगी और उन 29 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिन्हें राहुल गांधी की 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कवर नहीं किया गया था। हरिप्रसाद के अनुसार, राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इसके बाद 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक के गुंडलुपेट पहुंची। उनके मुताबिक,

21 अक्टूबर तक कर्नाटक के 11 जिलों में करीब 600 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान आम लोगों से संवाद किया गया और उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने कहा कि उसी यात्रा की स्मृति और जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कर्नाटक में 'भारत जोड़ो यात्रा 2.0' आयोजित की जा रही है। उनके अनुसार, इस चरण में कांग्रेस ने उन 84 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। यात्रा के दौरान दोपहर एक बजे से शाम तक जनसभाएं आयोजित किए जाने की बात भी उन्होंने कही। शिकारीपुरा से होगी शुरुआत हरिप्रसाद ने बताया कि शिकारीपुरा तालुक से की जाएगी। उनके अनुसार, कार्यक्रम में मंत्री मधु बंगारप्पा, रुद्रप्पा लमानी, जमीर अहमद खान, बी.एल. शंकर सहित अन्य वरिष्ठ नेता और स्थानीय पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके बाद 4

से 5 अक्टूबर के दौरान यात्रा को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों तक ले जाने की योजना है। शिकारीपुरा से शुरुआत के कारण के संबंध में पूछे गए सवाल पर हरिप्रसाद ने इसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र से जोड़ते हुए भाजपा की कथित कमियों और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान के रूप में बताया। उनके इस बयान को कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। 84 क्षेत्रों में 84 दिन का कार्यक्रम यात्रा की अवधि के बारे में पूछे जाने पर हरिप्रसाद ने कहा कि 'यह यात्रा 84 विधानसभा क्षेत्रों में 84 दिनों तक चलेगी।' इस दौरान पार्टी की ओर से स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क, पदयात्रा और जनसभाओं के आयोजन की योजना बताई गई है। मीडिया सम्मेलन में पूर्व एमएलसी नाययणस्वामी तथा KPCC मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख रमेश बाबू भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और बाद में जम्मू-कश्मीर तक पहुंची थी। समकालीन रिपोर्टों के अनुसार इस यात्रा ने कई राज्यों को कवर किया था।



वरथुर-गुंजूर में विकास कार्यों को गति, विभागीय समन्वय पर जोर



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026। वरथुर-गुंजूर क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने तथा निर्माण कार्यों के दौरान आम लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त लोखंडे स्नेहल सुधाकर ने की। बैठक में सड़क एवं पुल निर्माण की प्रगति के साथ भूमि अधिग्रहण, बिजली व जल

किया जाए। उपयोगिता स्थानांतरण का काम जल्द पूरा करने पर जोर संपत्तियों के दस्तावेजों और माप की जांच कर लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिन संपत्ति मालिकों को टीडीआर नहीं मिला है, उनके मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। लंबित अनुमतियों और एसडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा सरकारी स्तर पर लंबित अनुमतियों और निर्णयों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने तथा संबंधित मामलों का लगातार अनुसरण करने के निर्देश दिए गए। एसडब्ल्यूडी पुलिया से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को मौके पर स्थिति से संबंधित समस्याओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आवश्यक जल पाइपलाइन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि निर्माण गतिविधियों के दौरान स्थानीय निवासियों की जलापूर्ति प्रभावित न हो। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी सड़क और पुल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि

से जुड़े मामलों पर भी बैठक में चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को संपत्तियों के दस्तावेजों और माप की जांच कर लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिन संपत्ति मालिकों को टीडीआर नहीं मिला है, उनके मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। लंबित अनुमतियों और एसडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा सरकारी स्तर पर लंबित अनुमतियों और निर्णयों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने तथा संबंधित मामलों का लगातार अनुसरण करने के निर्देश दिए गए। एसडब्ल्यूडी पुलिया से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को मौके पर स्थिति से संबंधित समस्याओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आवश्यक जल पाइपलाइन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि निर्माण गतिविधियों के दौरान स्थानीय निवासियों की जलापूर्ति प्रभावित न हो। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी सड़क और पुल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि

केआरडीसीएल, एसडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस विभाग और जीबीए के संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों को संबंधित कार्यस्थलों और समस्याग्रस्त स्थानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यातायात और जनसुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश निर्माण कार्यों के दौरान वाहन चालकों और आम नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर आवश्यक यातायात प्रबंधन व्यवस्था करने को कहा गया। सड़क निर्माण के दौरान धूल, कीचड़ और अन्य असुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए गए। निर्माण स्थलों पर आम लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए आवश्यक व्यवस्था करने तथा सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया। सीवेज और अवैध कचरा फेंकने की समस्या पर कार्रवाई कुछ क्षेत्रों में सीवेज के पानी किया जाएगा। निरीक्षण में लोखंडे स्नेहल सुधाकर के नेतृत्व में बैंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेंज बोर्ड,

पर निरीक्षण कर समस्या वाले स्थानों की पहचान करने तथा अवैध कचरा डंपिंग के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि सड़क, पुल, जलापूर्ति, जल निकासी, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाए। विभागों के बीच आवश्यक सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान करने से एक परियोजना के कारण दूसरी परियोजना में बाधा आने की स्थिति को कम किया जा सकेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वरथुर-गुंजूर क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं का संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही, निर्माण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ें और परियोजनाओं के दौरान आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बैंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेंज बोर्ड, केआरडीसीएल, एसडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दादा गुरुदेव की पूर्णिमा भक्ति में गुंजे भक्ति गीत, श्रद्धा से अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026। श्री जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, बसवनगुडी के तत्वावधान में श्री जिनदत्त कुशल सूरी जैन सेवा एवं संगीत मंडल द्वारा दादा गुरुदेव की पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति एवं आराधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंडल के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लेकर दादा गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान मंडल के अध्यक्ष ललित डाकलिया ने गुरु भक्ति के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गुरु भगवंतों की कृपा और आशीर्वाद व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। दादा गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने तथा आत्मकल्याण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से गुरु भक्ति और धार्मिक संस्कारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। भक्ति गीतों से आध्यात्मिक हुआ वातावरण कार्यक्रम में सनी रांका, नितेश बोहरा, सुरेश कोठारी, नितिन बेंगानी, महावीर पारख, पारस पारख और जीतू बेंगानी ने सुमधुर स्वर में परमात्मा एवं दादा गुरुदेव की भक्ति से जुड़े गीतों की प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों से कार्यक्रम स्थल का वातावरण आध्यात्मिक और भावपूर्ण हो गया। उपस्थित श्रद्धालु भक्ति रस में भावविभोर नजर आए। गीत-संगीत के बीच श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से दादा गुरुदेव की आराधना की और पूर्णिमा भक्ति का लाभ लिया। कार्यक्रम में संघ एवं मंडल के अनेक सदस्य और श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान धार्मिक आस्था, भक्ति और सामूहिक आराधना का वातावरण बना रहा। समाचार प्रेषक ललित डाकलिया, बैंगलुरु।

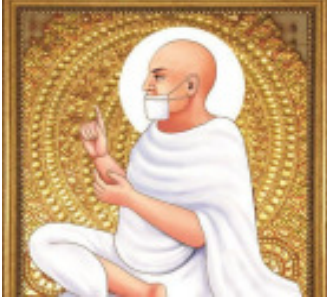


आचार्य भगवंतों के दर्शन-वंदन से धन्य हुआ ब्यावर संघ, धर्मचर्चा मेंमिला आध्यात्मिक मार्गदर्शन

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026। श्री ब्यावर संघ, बैंगलुरु के सदस्यों ने हलसूर में विराजमान जय गच्छाधिपति आचार्य प्रवर प. पू. श्री पार्श्वचंद्र जी म. सा. एवं प. पू. श्री पदमचंद्र जी म. सा. के दर्शन-वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संघ सदस्यों ने आचार्य भगवंतों के सान्निध्य में धर्मचर्चा एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन का लाभ लिया। आचार्य भगवंतों ने अपने मंगल मार्गदर्शन में कहा कि संतों का सान्निध्य व्यक्ति के जीवन को धर्म और सदाचार की दिशा में प्रेरित करता है। गुरु भगवंतों के दर्शन, वंदन एवं प्रवचन श्रवण से आत्मिक शांति के साथ संयम, सदाचार और धर्म के प्रति श्रद्धा को दृढ़ करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने संघ के सदस्यों को आपसी प्रेम, एकता और सौहार्द बनाए रखते हुए धर्म आराधना में निरंतर आगे बढ़ने

का संदेश दिया। गुरु सान्निध्य को बताया सौभाग्य श्री ब्यावर संघ के अध्यक्ष ललित डाकलिया ने कहा कि गुरुदेव के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करना संघ के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि संतों के सान्निध्य से संघ के सदस्यों में आध्यात्मिक चेतना और नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं एवं संघ के सभी सदस्यों से गुरु भगवंतों के बताए मार्ग पर चलने तथा संघ की एकता और धार्मिक गतिविधियों को



भजनों से गुंजा पैलेस ग्राउंड, श्री शांतिनाथजी महाराज की पुण्यतिथि पर उमड़ी श्रद्धा



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026। राजस्थान राजपूत संघ, बैंगलुरु की ओर से श्री श्री 1008 पीर श्री शांतिनाथजी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पैलेस ग्राउंड गेट नंबर 6 पर भव्य जागरण का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या

में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्री शांतिनाथजी महाराज के दर्शन कर भक्ति कार्यक्रम का लाभ लिया। जागरण के लाभार्थी श्री शांतिनाथजी भक्त मंडल रहे। इस अवसर पर भक्त मंडल की ओर से राजस्थान राजपूत संघ का सम्मान किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने सम्मान के लिए भक्त मंडल का आभार व्यक्त करते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में

सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। भक्ति गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल जागरण में राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार जोगभारती और गीता गोस्वामी ने श्री नाथजी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दीं। भजनों के दौरान पंडाल में श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए। नाथजी महाराज के जयकारों से आयोजन स्थल का

वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने देर तक भक्ति संगीत और भजनों का आनंद लिया। संघ के पदाधिकारियों ने भी आयोजन में सहयोग किया। कार्यक्रम में राजस्थान राजपूत संघ के अध्यक्ष सुजानसिंह भाटी, उपाध्यक्ष चेलसिंह चौहान, सहसचिव चंदनसिंह चौहान, सहकोषाध्यक्ष गणपतसिंह दहिया तथा मीडिया प्रभारी दलपतसिंह दहिया को पदाधिकारी मौजूद रहे। कमेटी सदस्य भानसिंह, चंदनसिंह चौहान, महेंद्रसिंह राठौड़, मेगसिंह दहिया, नरपतसिंह राठौड़, राजसिंह, चेलसिंह राणावत, गजेंद्रसिंह चौहान, कमलसिंह चौहान, पोकरसिंह भायल, चंदनसिंह राठौड़, भंवरसिंह सोलंकी एवं अर्जुनसिंह चौहान सहित अन्य सदस्य भी

अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान सुभाष राय और लीलाधर मंडलोई को, नारायण साव व सीमा मिश्र भी सम्मानित होंगे

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026। बैंगलुरु की हिंदी रचनाकारों की साहित्यिक संस्था 'शब्द' ने वर्ष 2026 के अपने प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संस्था के अध्यक्ष डॉ. श्रीनारायण समीर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 'अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान' इस वर्ष संयुक्त रूप से जीवनीकार सुभाष राय और कवि-लेखक लीलाधर मंडलोई को प्रदान किया जाएगा। वहीं 'दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान' के लिए भाषा-सेवी नारायण साव तथा प्रथम 'राजस्थान गौरव पुरस्कार' के लिए जयपुर की लोक गायिका सीमा मिश्र का चयन किया गया है। एक लाख रुपये का 'अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान' सुभाष राय को उनकी कृति 'दिगम्बर विद्रोहिणी अक्क महादेवी' तथा लीलाधर मंडलोई को उनकी आत्मकथा 'जब से आँख खुली हैं' के लिए दिया जाएगा। दोनों साहित्यकारों को पुरस्कार स्वरूप 51-51 हजार रुपये के साथ पारंपरिक मैसूरु पेटा, स्मृति चिह्न, श्रीफल और अंगवस्त्रम् प्रदान किए जाएंगे। नारायण साव को हिंदी सेवा सम्मान 'शब्द' के दूसरे प्रतिष्ठित सम्मान 'दक्षिण भारत शब्द हिंदी

सेवी सम्मान' के लिए इस वर्ष नारायण साव का चयन किया गया है। उन्हें सम्मान प्रतीकों के साथ 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि बैंगलुरु और चेन्नई से प्रकाशित 'दक्षिण भारत राष्ट्रमत' अखबार समूह के सौजन्य से दी जाएगी। सीमा मिश्र को पहला राजस्थान गौरव पुरस्कार डॉ. श्रीनारायण समीर ने बताया कि 'शब्द' की ओर से अब प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये का 'राजस्थान गौरव पुरस्कार' भी प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान राजस्थान में कला, संस्कृति, संगीत, समाजसेवा

आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली किसी एक हस्ती को दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत जयपुर की प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष 'अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान' के लिए 53 प्रविष्टियां और 'दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान' के लिए 11 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। प्राप्त प्रविष्टियों पर समग्र विचार के बाद बाबूलाल गुप्ता, श्रीकांत पाराशर, नलिनी पोपट, डॉ. उषारानी राव और डॉ. श्रीनारायण समीर के निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से पुरस्कार विजेताओं का चयन किया। चयन में संबंधित रचनात्मक कार्यों के मूल्यांकन के साथ साहित्य और भाषा के क्षेत्र में अब तक के योगदान को भी आधार बनाया गया। निर्णायक मंडल की संस्तुति के अनुसार सुभाष राय ने अक्क महादेवी के जीवन और उनके वचनों के हिंदी भावांतरण के माध्यम से रूढ़ी जीवन की पीड़ा और विद्रोह को साहित्यिक विमर्श में प्रमुखता देने का कार्य किया। वहीं लीलाधर मंडलोई की आत्मकथा में विस्थापित खान-मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के संघर्षों को व्यापक रूप में प्रस्तुत किए जाने को उल्लेखनीय माना गया। मंडल के अनुसार नारायण साव का दक्षिण क्षेत्र तथा हिंदीतर प्रदेशों के विभिन्न प्रतिष्ठानों के कामकाज में हिंदी को प्रभावी भाषा बनाने में योगदान रहा है। वहीं सीमा मिश्र की लोक गायकी को राजस्थान और सीमावर्ती गुजरात के मरुक्षेत्र के लोकजीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित किया गया है।

बैंगलुरु में ट्रैफिक का दबाव सोसायटी के गेट तक, बाहर निकलने में लगा आधा घंटा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बैंगलुरु, 28 सितंबर 2026। बैंगलुरु की ट्रैफिक समस्या अब केवल प्रमुख सड़कों और चौराहों तक सीमित रहने की चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने आवासीय परिसरों के भीतर वाहनों की आवाजाही पर भी ध्यान खींचा है। वीडियो में एक आवासीय सोसायटी के परिसर के अंदर कारों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, जहां वाहन धीमी गति से आगे बढ़ते नजर आते हैं। वीडियो साझा करने वाली महिला के अनुसार, सोसायटी के समय कुछ लोगों को दोपहर के भीतर से मुख्य गेट तक पहुंचने और परिसर से बाहर निकलने में करीब 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि, वीडियो में दिखाई गई स्थिति एक विशेष आवासीय परिसर से संबंधित है और इसके आधार पर पूरे बैंगलुरु की सभी सोसायटियों की स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। सोसायटी के भीतर भी वाहनों का दबाव वीडियो में बड़ी संख्या में कारों एक-दूसरे के पीछे खड़ी दिखाई देती हैं। वाहनों की धीमी रफ्तार के कारण परिसर के अंदर ही लंबी कतार बन गई। सामान्य तौर पर आवासीय सोसायटियों के प्रवेश और निकास द्वार मुख्य सड़कों से जुड़े होते हैं। ऐसे में बाहर की सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ने पर उसका असर गेट के आसपास की आंतरिक आवाजाही पर भी पड़ सकता है। बैंगलुरु में रोजाना बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों से कार्यालयों,

दबाव का स्थायी समाधान नहीं है। सार्वजनिक परिवहन की पहुंच, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग और यातायात मार्गों और आवासीय इलाकों पर भी गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते शहर के साथ बढ़ती चुनौती बैंगलुरु में नए आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसके साथ ही निजी वाहनों की संख्या और दैनिक करते महानगर में आवासीय क्षेत्रों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के बीच बेहतर समन्वय को यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल सड़कों का विस्तार ही यातायात

